स्मार्ट सिटी का झुनझुना बजता रहेगा, शहर में कबाड़खाना ज्यों का त्यों जमा रहेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के पहले चरण में 20 शहर चुने गये हैं। दो साल तक चली इस कवायद मे स्थानीय नगर निगम ने भी इनमें स्थान पाने के लिये खूब बाज़ीगरी दिखाई। किसी गायिका को ब्रेंड एम्बैसेडर बनाया तो किसी कम्पनी को सुझाव देने का ठेका दिया और कई बार इस विषय पर सम्मेलन तथा विचार गोष्ठियां की गयीं। इससे सम्बन्धित फ़ार्म छपवाने व जनता से भरवाने के लिये निगम स्टाफ़ को पेले रखा। मीडिया के द्वारा जमकर प्रचार किया। जाहिर है इस सारी ड्रामेबाज़ी पर निगम ने करोड़ों रुपया फ़ूंक दिया।

परन्तु जो काम करने वाले थे उनमें से एक भी नहीं किया। अवैध निर्माणों को हटाना व बनने से रोकना, सरकारी ज़मीनों, फुटपाथों, सड़कों आदि पर अवैध कब्ज़े हटाने जैसे मामूली काम निगम से नहीं हो पाये। 'मज़दूर मोर्चा' ने अनेकों बार प्रकाशित किया है कि यदि निगम अफ़सरों की रिश्वतखोरी और हरामखोरी बन्द हो जाय तथा कानून-कायदों का सही ढंग से पालन हो जाय तो शहर स्वत: स्मार्ट बन जायेगा। न केवल शहर, इसी तर्ज़ पर चलने से पूरा देश ही स्मार्ट हो जायेगा।

एनएच-5 की रेलवे रोड पर स्थित नगर निगम के एक स्टोर-दफ़्तर का है। इसके सामने करीब 100 फ़ीट तक सड़क किनारे निगम ने अपना कबाड़ा बिखेर रखा है। इसी से प्रेरित होकर इसी सड़क पर स्थित प्लाट नम्बर 5सी-5बीपी अमृत जल फैक्टरी व इसके बगल में 5-सीपी-5 प्रोग्रेसिव फाईबर, 5/123 व 5/105 नेसन हट ने अपने सामने कबाड़, बोतलें, लोहा व अन्य सामान बिखेर रखे हैं। इसी तरह एन एच-2 स्थित वृद्ध आश्रम के निकट सड़क पर कबाड़े के ढेर लगे रहते हैं और जब इस कबाड़े को ट्रक में लादा जाता है तो वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये चन्द तो केवल उदाहरण हैं, शहर भर में ऐसे कब्ज़े बेशुमार हैं।

गत सप्ताह नगर निगम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में तोड़-फ़ोड़ अभियान चला कर ऐसे ही कुछ कब्ज़ों को हटाने का आधा-अधूरा सा प्रयास किया है। इस अभियान में भेदभाव, यानी एक को तोड़ दिया और दूसरे को छोड़ दिया, की भी काफ़ी शिकायतें सुनने में आ रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि तोड़-फ़ोड़ के तुरन्त बाद लोग़ों ने फ़िर से कब्ज़े कर लिये हैं। इस तरह का आधा-अधूरा अभियान चलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। निगम को यदि यह अभियान चलाना है तो इसमें अपनी समुचित कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चालान करे, जहां आवश्यक हो गिरफ़्तारियां करे, सामान को जब्त करे तथा तोड़-फ़ोड़ का खर्चा भी वसूले। विदित है कि शहर में ऐसे दुकानदारों की कमी नहीं है जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे की फुटपाथ एवं सड़क पर अपना सामान तो सज़ा ही रखा है; इसके अलावा अपने सामने की जगह हज़ार से दो हज़ार रुपये प्रति दिन किराये पर भी उठा रखी है। निसंदेह यह सारा धंधा स्थानीय नेताओं और भ्रष्ट अफ़सरों की मिलीभगत से चल पा रहा है।

नवनियुक्त निगम आयुक्त आदित्य दहिया से शहर को कुछ उम्मीद बंधी है, देखना है कि स्थानीय नेता उन्हें कहां तक काम करने देते हैं।

गुड़ नहीं तो गुड़ से जुमले हैं खट्टर के पास

पेज एक का शेष

कॉलेज और महिला कॉलेज में स्टाफ़ व आवश्यक सुविधाओं के अभाव को लेकर छात्र आये दिन आन्दोलन करने को मजबूर होते हैं । पलवल तथा खेड़ी गूजरान में करोडों की लागत से कॉलेज भवन तो बनाकर खड़े कर दिये लेकिन शिक्षण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। राज्य भर में कुल 115 कॉलेज तो सरकार ने 'खोल' दिये लेकिन प्रिंसिपल कुल 25 ही हैं, शेष सभी बिना प्रिंसिपल के 'चलाये' जा रहे हैं।

मुजेसर रेलवे फ़ाटक के स्थान पर अंडरपास की बात करना आसान है लेकिन सरकारी काम-काज का नमूना मेवला महाराजपुर के अंडरपास पर देखा जा सकता है। वहां रेलवे ने (अपनी लाइनों के नीचे) पुल का सबसे कठिन काम काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है जो आगामी 6 से 8 माह तक पूरा कर लिया जायेगा; परन्तु हरियाणा सरकार द्वारा दोनों ओर बनाये जाने वाले रैंपों के काम का कोई ठिकाना नहीं। अभी तो सरकार के दो विभागों-हूडा और नगर निगम-में ही बजट को लेकर झगड़ा चल रहा है।

मनोहर लाल खट्टर यदि शहर-शहर जाकर जुमले फेंकने की बजाय अपने दफ़्तर में बैठ कर कुछ प्रशासनिक काम करें और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को सुधारें तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। जुमलेबाज़ी करने और उद्घाटनों के लिये नारियल जेब में लिये घूमने वाले तथाकथित नेताओं की किसी भी शहर में कोई कमी नहीं, फ़िर यहां तो केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल हैं ना।

बसें तो चलती नहीं कृष्णपाल रेल मन्त्री से गुहार का ढिंढोरा!

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल गूजर को पौने दो साल सत्ता-सुख भोगने के बाद अब अचानक पता चल गया कि उनके क्षेत्र में पूर्व (बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश) के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये लोग बार-त्योहार व खुशी-गमी में अपने गांवों में भी जाते हैं। इसके लिये यहां से किसी सीधी ट्रेन की व्यवस्था न होने के चलते इन्हें दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने में न केवल कठिनाई होती है बल्कि समय और पैसा भी बर्बाद होता है।

कृष्णपाल को इन लोग़ों की तकलीफ़ एवं यहां से सीधी ट्रेन चलाने की मांग का 'ज्ञान' अचानक इसलिये हो गया कि इस माह आने वाले रेल बजट में रेल मंत्रालय फ़रीदाबाद से पटना के लिये सीधी ट्रेन चलाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इलाके का जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्रालय ने यह जानकारी कृष्णपाल को दे दी। बस, सूचना मिलते ही सांसद महोदय ने तमाम अखबारों के माध्यम से प्रचार शुरू करा दिया कि उन्होंने रेल मन्त्री सुरेश प्रभु से मिलकर उक्त सीधी ट्रेन चलाने की मांग रख दी है। जाहिर है ट्रेन के चल जाने पर कृष्णपाल अपनी पीठ थपथपाते हुए पुर्बिया वोट बैंक पर अहसान जता पायेंगे।

उक्त सीधी ट्रेन चल जाये बहुत अच्छी बात है। रेलवे का कुछ मुनाफ़ा बढने के साथ-साथ यात्रियों को सुविधा हो जाय इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसके लिये कृष्णपाल का एहसान, झूठ-मूठ का ही सही, मानने में भी किसी का क्या जाता है ? एहसान तो शहर की जनता और भी मानने को तैयार है यदि वे 6 साल से अधर में लटकी पड़ी चौथी लाइन को भी पूरा करा देते। बरसों से ओल्ड फ़रीदाबाद रेलवे स्टेशन की अधबनी बिल्डिंग को पूरा कराने के साथ-साथ शहर के स्टेशनों पर पुल जैसी सामान्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करा देते।

भगवान कृष्ण के नाम से जुड़े दो नगरों-मथुरा व कुरूक्षेत्र के बीच सीधी ट्रेन चलने से धार्मिक पर्यटन का तो पता नहीं, लेकिन दैनिक यात्रियों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। स्थानीय नागरिक होने के नाते कृष्णपाल से उन दैनिक यात्रियों की दुर्दशा छिपी न होगी जिन्हें भूसे की तरह ठूंस-ठूंस कर शटल ट्रेनों में सफ़र करना पड़ता है। इतना ही नहीं अक्सर इन शटल ट्रेनों के लेट अथवा रद्द हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। मैट्रो रेल व अन्य साधन अपेक्षाकृत काफ़ी महंगे होने के चलते अधिकांश लोग इन्हीं ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, यदि कृष्णपाल अपनी 'तीव्र गतिशील' सरकार से कुछ करवा देते तो जनता जरूर एहसानमंद हो जाती । चलो दो सालों में नहीं तो अगले तीन सालों में भी जनता इनकी करनी और कथनी को खूब अच्छी तरह परख लेगी।

गत विधान सभा चुनाव से पूर्व क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने के लिये मंझावली के निकट यमुना नदी पर पुल का शिलान्यास केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी से कराया था। वैसे इस पुल की आधारशिला बीसियों बरस पूर्व राजेश पायलेट ने भी रख दी थी। इसी बात को याद दिलाते हुए मोदी के इन दोनों-गडकरी व कृष्णपाल-जुमलेबाज़ों ने कहा था कि दो साल में पुल बन कर चालू हो जायेगा। उस वक्त 'मज़दूर मोर्चा' ने स्पष्ट लिख दिया था कि दो साल में यदि यह सरकार पुल की डीपीआर (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ही तैयार कर ले तो बड़ी बात होगी। वही बात आज सामने है कि अभी तक इन जुमलेबाज़ों से डीपीआर नहीं बनी। पुल के लिये आवश्यक आसपास की ज़मीन का अधिग्रहण तक नहीं हो सका है। समझा जाता है कि दो साल बाद यानी चुनावी वर्ष में ये लोग इस (पुल) स्थल पर कुछ ड्रामेबाज़ी करके जनता को फ़िर से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह जनता है सब जानती है। अन्दर क्या है बाहर क्या है, सब जानती है।

रेल मन्त्री से गुहार करने तो मन्त्री जी झट से पहुंच गये लेकिन जो बसें चलाना उनकी हरियाणा सरकार का दायित्व एवं एकाधिकार है, उसकी ओर से मन्त्री जी आंखें मूंदे बैठे हैं। सड़क परिवहन पर एकाधिकार जमाये बैठी हरियाणा सरकार की रोडवेज़ बस सेवा आज अपने बद्तरीन हालात से गुजर रही है इसका खमियाज़ा सीधे तौर पर तो बसों में सवारी करने वाले यात्री भुगत रहे हैं और राजस्व घाटे के रूप में पूरे प्रदेश की जनता। बल्लबगढ से अलीगढ रूट पर हरियाणा रोडवेज बसों के 10 फ़ेरे लगते थे जो 31 जनवरी से बिल्कुल बन्द हैं। जबकि 50 फ़ेरे यूपी रोडवेज़ की बसों के लगते थे, इनमें से भी 6 फ़ेरे घट गये हैं। झगड़ा दोनों राज्यों के परिवहन विभाग का है, इनके परमिट सिस्टम का है।

परमिट सिस्टम बनाने वाले शासक वर्ग को केवल अपनी परमिट फ़ीस एवं लूट कमाई की चिन्ता है, उसे यात्रियों के आवागमन में होनवाली असुविधा की कोई चिन्ता नहीं। उनके लिये परिवहन व्यवस्था यात्रियों के लिये नहीं बल्कि यात्री परिवहन व्यवस्था के लिये हैं। खुद सरकारी वाहनों में घूमने वाले शासकों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि इस रूट पर बसों के कम हो जाने या बन्द हो जाने पर उन ग़रीब यात्रियों का क्या होगा जो महंगी कारों में सफ़र नहीं कर सकते।

इस रूट के यात्री भटक रहे हैं लेकिन, अफ़सरों की तो छोड़िये, विधायक एवं सांसद (मंत्री) को भी इसकी चिंता नहीं। यूपी सरकार ने हरियाणा रोडवेज़ की बसों को अपने प्रदेश में ही तो घुसने से रोका है, अपनी सीमा तक आने से तो वह नहीं रोक सकती। यदि हरियाणा सरकार को ज़रा सी भी यात्रियों की परवाह होती तो इस रूट की तमाम बसों को बिल्कुल बंद कर देने की अपेक्षा यूपी सीमा तक तो चला ही सकती थी। यात्री वहां तक पहुंच कर आगे की कोई व्यवस्था जैसे-तैसे कर लेते। परन्तु ऐसा जनहितैषी उपाय करने की अपेक्षा इस रूट को बिल्कुल ही ठप कर दिया गया है।

हां, जुमलेबाज़ी और शोशेबाज़ी में इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं। कभी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ़्त सवारी का झांसा तो अब छात्राओं के लिये स्कूल व कॉलेज तक मुफ़्त यात्रा का जुमला। मुफ़्त यात्रा के शगूफ़े छोड़ने के बजाय यदि सरकार भाड़ा लेकर ही परिवहन सुविधा उपलब्ध करा दे तो बड़ी बात है। कोई साल ऐसा नहीं जाता होगा जब स्थानीय नेहरू कॉलेज के छात्रों को बस सेवा के लिये आन्दोलन न करना पड़ता हो। पिछले दिनों रोहतक की छात्राओं ने भी लचर बस सेवा के विरोध में अच्छा-खासा आन्दोलन छेड़ा था। इसके बाद ही सेवा में कुछ सुधार हो पाया था।

दो घंटे लेट पहुंची फ़ायर ब्रिगेड, तब तक सब खाक हो चुका था

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना मुजेसर के इलाके में शिव कॉलोनी (सेक्टर 23 के पीछे एवं जवाहर कॉलोनी को जोड़ने वाली बड़ी पुलिया के निकट) स्थित सीता राम अग्रवाल के प्लास्टिक दाना गोदाम एवं पैक्ट्री में 9 फ़रवरी को प्रात: साढे पांच बजे आग लग गयी। शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट से। गोदाम का ताला बंद था। मालिक अन्यत्र कहीं अपने घर में सोया था। गोदाम से उठता धुंआ देख कर पड़ोसियों ने तुरंत फ़ायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। घंटी गयी लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा किया तो फ़ोन व्यस्त था, बार-बार करने पर भी व्यस्त ही रहा। जाहिर है सुबह की मीठी नींद में फ़ोन की घंटी से पड़ने वाले खलल को रोकने के लिये फ़ोन का चोगा उठा कर एक तरफ़ रख दिया होगा।

मालिक व पुलिस को फ़ोन पर सूचित करने के साथ-साथ पड़ोसियों ने ताला तोड़ कर गोदाम की आग को बुझाने का, अपने स्तर पर प्रयास किया। आग के फ़ैलाव को रोकने के लिये प्लास्टिक दाने के कट्टों को बाहर निकाल कर दूर फ़ेकना शुरू कर दिया। इस दौरान भी फ़ायर ब्रिगेड को फ़ोन करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अन्त में करीब सवा सात बजे कामयाबी मिली, फ़ोन उठा और ठीक पौने आठ बजे फ़ायर ब्रिगेड की मात्र एक गाड़ी पहुंची। तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। यहां तक कि बाहर निकाल कर दूर फ़ेके गये कट्टों तक भी आग पहुंच चुकी थी।

फ़ायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर कुछ काबू पाया ही था कि उसका पानी समाप्त हो गया। दूसरी गाड़ी आने में 10 से 15 मिनट लग गये। इस बीच आग ने फ़िर से इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एक के बाद एक गाड़ियां लगातार आती रहीं, इसके बावजूद आग को बुझाने में करीब दो घंटे लग गये। तब तक सारा माल, करीब 25 लाख रुपये का, जल कर राख हो चुका था। इतना ही नहीं गोदाम के साथ लगते मकानों की दिवारें व लेंटरों में भी दरारें पड़ गयी। डर के मारे इन मकानों में रहने वालों ने भी अपने सामान बाहर निकाल लिये थे।

यदि फ़ायर ब्रिगेड वाले पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लेते और तुरन्त मौके पर पहुंच जाते तो मात्र एक गाड़ी से ही आग पर काबू पाया जा सकता था। इससे लाखों का माल स्वाहा होने से बच जाता और पड़ोसियों के घर भी दरारें पड़ने से बचे रह जाते। फ़ायर कर्मचारी इस पर सफ़ाई दे सकते हैं, यदि कोई पूछने वाला हुआ तो, कि उनके पास न तो पर्याप्त ड्राइवर हैं, न कर्मचारी, न ढंग की गाड़ी इत्यादि-इत्यादि। लेकिन सरकार एवं नगर निगम इस तरह का कोई बहाना बनाने का हक नहीं रखते। आग बुझाना नगर निगम की सामान्य सेवाओं में माना जाता है, परंतु गत 15-20 वर्षों से निगम ने 'अग्नि शमन' के नाम से एक विशेष टैक्स भी जनता पर लाद रखा है, उसके बावजूद इस तरह की लचर सेवा देना जनता के प्रति एक दंडनीय अपराध है। इसके लिये उत्तरदायी लोग़ों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिये तथा जिन-जिन लोग़ों का नुकसान हुआ है उनकी पूरी भरपाई होनी चाहिये। परन्तु जिस निगम के पास वेतन देने के लिये ही पैसों का अकाल पड़ा रहता है, वह भला किसे क्या मुआवज़ा देगा।

इतना ही नहीं, मुआवज़ा तो गया ऐसी तैसी में, निगम गोदाम मालिक से आग बुझाने का खर्चा भी मांगेगा। यदि कहीं बीमा क्लेम लेने के लिये गोदाम मालिक को फ़ायर अफ़सर से रिपोर्ट लेनी पड़ गयी तो उसकी रिश्वत व जूता घिसाई अलग से। इस बात की भी पूरी संभावना है कि गोदाम मालिक को ही, रिहायशी इलाके में अवैध रूप से फ़ैक्ट्री एवं गोदाम बनाने का दोषी ठहरा दिया जाय। यदि वह दोषी है तो निगम भी कम दोषी नहीं है जो उससे कमर्शियल गृहकर तो नियमित रूप से लेता रहा परन्तु उसे वहां फ़ैक्ट्री चलाने से कभी रोका नहीं। रिहायशी इलाके में इस तरह की अवैध फ़ैक्ट्रियां एवं गोदाम यही एकमात्र नहीं था। बल्कि सैंकड़ों हज़ारों की संख्या में और भी मौजूद है तथा लगातार बढते जा रहे हैं।